www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 178 | जौनपुर गुरूवार, 12 फरवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

वंदे मातरम को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वंदे मातरम को लेकर सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। इनके तहत राष्ट्रगान से तुरंत बाद 6 छंदों वाला वंदे मातरम गाया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि इस दौरान सभी को खड़ा होना अनिवार्य होगा। गीत कुल 3 मिनट 10 सेकंड का है। खबर है कि नियमों में बताया गया है कि अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक साथ गाए जाने हैं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। शुरू में वंदे मातरम की रचना स्वतंत्र रूप से की गई थी और बाद में इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ (1882 में प्रकाशित) में शामिल किया गया। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को किया गया था। 1950 में संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। वंदे मातरम को कई आधिकारिक कार्यक्रमों में गाया जाना अनिवार्य किया गया है। इनमें ध वजारोहण के दौरान, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आने से पहले और जाने के बाद, राज्यपालों के आने से पहले और जाने के बाद शामिल है। पद्म पुरस्कार जैसे समारोहों के दौरान भी वंदे मातरम गाया जाना जरूरी है। इसके अलावा सरकार ने कार्यक्रमों की सूची भी जारी की है।गाने और नारेदोनों के तौर परवंदे मातरम के बढ़ते प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत की सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने या बोलने पर रोक लगाने वाले परिपत्र जारी किए।

यूपी में बनेगी अखिलेश सरकार

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि पिछले साल जो बजट पेश हुआ था, उसमें 40 प्रतिशत राशि किसी भी विभाग में खर्च नहीं हुई।एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के यूपी आने के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि एआईएमआईएम भाजपा की बी–टीम की तरह काम कर रही है। भाजपा और एआईएमआईएम मिलकर प्रदेश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। सपा ही भाजपा का असली विकल्प है। सभी वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं। यूपी में हमारी सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।एआईएमआईएम के आने से सपा के वोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पार्टी सिर्फ वोटों का बंटवारा करती है ताकि भाजपा को लाभ मिल सके। एआईएमआईएम नेता शौकत अली के बयान पर सपा नेता ने कहा कि हर किसी को उतने बच्चे पैदा करने का अधिकार है जितने वह चाहते हैं, लेकिन इस पर कोई कानून नहीं है। तो किसी को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, इस पर बयान देने की क्या जरूरत है। भारत–पाकिस्तान मैच को लेकर सपा नेता ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष

गहरे सदमे में हूं, भारत ने दिया एकजुटता का संदेश : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कनाडा में हुए स्कूल में गोलीबारी की घटना के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस त्रासदी पर गहरा दुख जताते हुए कनाडा के लोगों के साथ भारत की एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा में हुई इस भयावह गोलीबारी से मैं बेहद स्तब्ध हूं। मैं अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस दुख की घड़ी में भारत कनाडा के लोगों के साथ खड़ा है। ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तर–पूर्वी हिस्से में स्थित एक दूरस्थ

पहाड़ी कस्बे टम्बलर रिज के एक हाई स्कूल में हुई सामूहिक गोलीबारी के बाद उन्होंने ये बयान दिए हैं। इस गोलीबारी में कम से कम 10 लोग मारे गए, जिसे दशकों में कनाडा की सबसे घातक स्कूल गोलीबारी बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर स्कूल पहुंचने पर उन्हें छह लोग मृत और दर्जनों घायल मिले। एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। अधिकारियों ने बाद में बताया कि कस्बे के एक घर से दो और शव बरामद किए गए, जिनका संबंध कथित तौर पर संदिग्ध से है। हमलावर स्कूल में मृत पाया गया, पुलिस के अनुसार उसने खुद को चोट पहुंचाई थी। दो पीड़ितों को गंभीर या जानलेवा चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया, जबकि लगभग 25 अन्य लोगों का स्थानीय चिकित्सा केंद्र में इलाज किया गया। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है, लेकिन हमलावर छात्र था या नहीं, इस बारे में कोई और जानकारी जारी नहीं की है। अधिकारियों ने यह भी पुष्टि नहीं की है कि मृतकों में कितने बच्चे थे।

सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे बिरला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद का बजट सत्र जारी है। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया, जिसके बाद अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में खामियां सामने आई है, जिसके संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए है। इस बीच अब लोकसभा सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दोषपूर्ण नोटिस को खारिज होने से बचाने के लिए उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया और त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। लोकसभा सचिवालय सूत्र के मुताबिक विपक्षी सांसदों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले नोटिस में कमियां पाई गई हैं। नोटिस में फरवरी 2025 की घटनाओं का चार बार जिक्र है, जिसके आधार पर नियमों के मुताबिक इसे खारिज किया जा सकता था। हालांकि, स्पीकर ने सचिवालय को नोटिस की कमियों को ठीक करने और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ओम बिरला ने नियमों के मुताबिक तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद नोटिस को लिस्ट किया जाएगा। बदला हुआ नोटिस मिलने के बाद तय नियमों के मुताबिक इसकी तुरंत जांच की जाएगी। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। बता दें कि 13 फरवरी को बजट सत्र के पहले सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और 9 मार्च को चर्चा की जा सकती है। मंगलवार (10 फरवरी) को कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। सूत्रों के अनुसार विपक्षी सांसदों ने स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी गई।

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा यूपी का बजट, हर वर्ग का होगा विकास : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार बुधवार को विधानसभा में राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा और लंबे समय से लंबित सभी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा। ब्रजेश पाठक ने आईएएनएस से कहा कि यह बजट गरीब आदमी के आम जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बजट श्विकसित भारतश् के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने जिन संकल्पों को जनता के सामने रखा था, उन्हें इस बजट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा है। विपक्ष पूरी तरह विफल हो चुका है और उसकी सोच उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बनाए रखने की रही है, जबकि मौजूदा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा दे रही है। वहीं, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए है। उन्होंने बताया कि महिलाओं, किसानों, युवाओं, वंचित वर्गों और श्रमिक वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने पूंजीगत निवेश (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) पर भी खास ध्यान दिया है, क्योंकि जितना अधिक पूंजी निवेश होगा, उतने ही नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्ष से अपील की कि कम से कम बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सहयोगात्मक रवैया अपनाए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों से की अपील

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाबवासियों से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा हर परिवार के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के बारे में पंजाब विरोधी ताकतों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार से गुमराह न हों। एक वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब सरकार ने लोक भलाई वाली इस प्रमुख योजना की शुरुआत की है ताकि पंजाब के हर नागरिक, खास तौर पर समाज के कमजोर वर्गों को कैशलेस इलाज तक सीधी पहुंच मिल सके।इस पहल के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना'

शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इसके तहत पंजाब का हर परिवार 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकता है।" इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब व्यापक स्तर पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह योजना लोगों पर वित्तीय बोझ को काफी कम करेगी और साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करेगी।"इस योजना में रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और अन्य नागरिक स्वास्थ्य कार्ड के लिए पात्र हैं। यह स्वास्थ्य कार्ड सुविधा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों से या आधार कार्ड या वोटर कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।लोगों से मिल रहे उत्साह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का पंजाब के लोगों ने भरपूर स्वागत किया है और लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल ने उन परिवारों को बड़ी राहत पहुंचाई है, जिन्हें पहले बीमारी के इलाज का भारी खर्च अपनी जेब से देना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने भ्राम जानकारी फैलाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि राज्य के लोगों को ऐसी सुविधाएं मिलें,

किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए बड़ी पहल, टास्क फोर्स गठित करेगी सीएम फडणवीस की सरकार

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या देशभर के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में अब इसे रोकने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के कृषि विभाग ने एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इस टास्क फोर्स का काम किसानों की मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक कठिनाई, सामाजिक तनाव और जलवायु बदलाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियां बनाना होगा। देखा जए तो राज्य सरकार की यह पहल किसानों को सिर्फ राहत देने तक सीमित नहीं, बल्कि उनके जीवन और आय को स्थायी रूप से सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। यह टास्क

फोर्स आगामी राज्य विधानसभा की बजट सत्र जो कि 23 फरवरी से शुरू होने वाले है, उससे पहले बनाई गई है। बता दें कि इस टास्क फोर्स का नेतृत्व एग्जेशन और ट्रेनिंग विभाग के निदेशक रफीक नाइकवाडी करेंगे। इसमें विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिसमें सुनील बोरकर, उदय देशमुख, गणेश घोरपड़े, जिवन बुंदे, नंदकिशोर नैनवाड, सत्यजीत शितोले, सोनाली शिलकर, कृषि समाजशास्त्री डॉ. विनायक हेगना और महिला किसानों की मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाली मनोरोग विशेषज्ञ सृष्टि दोइजाद का नाम शामिल है। कृषि आयुक्त सुरज मांढरे ने बताया कि कई योजनाएं पहले से लागू हैं, लेकिन आज किसान जलवायु परिवर्तन, फसल नुकसान, आर्थिक दबाव और सामाजिक तनाव जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए टास्क फोर्स 'चार–स्तरीय समेकित दृष्टिकोण' अपनाएगा। इसके तहत तकनीकी और कृषि में नई तकनीक, आर्थिक सहायता और स्थिरता, सामाजिक समर्थन और समुदाय सहयोग, और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस होगा। बात अगर टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य की करें तो इसका उद्देश्य किसानों की आत्महत्या के कारणों का अध्ययन और शोध करना, जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव का विश्लेषण और समाधान सुझाना, आत्महत्या रोकने के लिए रणनीतियां बनाना, तकनीक, वित्त और मानसिक स्वास्थ्य आपदा के समय तत्काल सहायता और आपदा के बाद पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाना होगा।

कांग्रेस के दबाव के बाद डीएमके का बड़ा एलान

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी–अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। इसी बीच तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने शीट शेयरिंग को लेकर बड़ी घोषणा की है। पार्टी ने कहा कि वह सीट–शेयरिंग वार्ता शुरू करने के लिए एक समिति बनाएगी। यह समिति 22 फरवरी से अपने काम की शुरुआत करेगी। बता दें कि इससे पहले डीएमके का प्रमुख सहयोगी कांग्रेस ने इस बात पर चिंता जताई थी कि चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस का कहना था कि उसने बातचीत शुरू करने की पहल की थी, लेकिन डीएमके की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस के टीएनसीसी और एआईसीसी इन–चार्ज नेता गिरीश चोडंकर ने कहा कि वह दिसंबर 2025 में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से मिलकर बातचीत करने के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई थी। लेकिन डीएमके की ओर से अब तक कोई समिति गठित नहीं की गई। गिरीश चोडंकर ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि यह दुखद है क्योंकि सीटों और उम्मीदवारों के बंटवारे की जल्दी तय करना

जरूरी था, ताकि चुनावी तैयारी समय पर हो सके। वहीं टीएनसीसी प्रमुख के सेल्वापेरुंथागई ने भी कहा कि बातचीत जल्दी शुरू करना जरूरी है, और अंतिम समय में सीटें तय करना चुनावी तैयारी को प्रभावित कर सकता है। वहीं इस मामले में डीएमके पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अपडेट पूरा हो चुका है। पार्टी के जिला सचिव, सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारी लगातार सदस्यता अभियान, बूथ एजेंट प्रशिक्षण और अन्य चुनावी गतिविधियों में लगे हैं।

कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के चौंबर में घुसकर गाली–गलौच की : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच अब स्पीकर के चौंबर में कथित हंगामे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि 20 से 25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चौंबर में जबरन घुसे और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। रिजिजू ने कहा कि वह खुद उस समय मौके पर मौजूद थे और स्पीकर इस घटना से बेहद आहत हैं। उनके अनुसार, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और स्थिति को और उकसाया गया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सदन की कार्यवाही नियमों से चलती है और बिना चेयर की अनुमति के कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि

संसद में आचरण और नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह प्रधानमंत्री हों या अन्य कोई सदस्य। रिजिजू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अपील की कि वे अपने नेताओं को संसदीय मर्यादा का पालन करने की सलाह दें। उन्होंने कहा कि संसद बच्चों की तरह व्यवहार करने की जगह नहीं है ।

राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का पलटवार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश की राजनीति में एक बार फिर डेटा सुरक्षा और अमेरिका–भारत व्यापार समझौता चर्चा के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के डेटा के साथ समझौता किए जाने के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के बयान पर जवाब देते हुए कहा भारत का डेटा श्डेटा प्रोटेक्शन एक्टश् के तहत सुरक्षित है। देश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों के अपने–अपने नियम हैं। आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। सरकार का स्पष्ट कहना है कि देश

की डेटा संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है। बुधवार को लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भारत की ताकत को जनता और डेटा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि 1.4 अरब लोगों का देश सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही नहीं, बल्कि डेटा के विशाल भंडार के कारण भी वैश्विक शक्ति बन सकता है। उन्होंने एआई की तुलना इंजन से करते हुए कहा कि जैसे इंजन को पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही एआई को डेटा की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास पेट्रोल यानी डेटा नहीं है, तो एआई बेकार है। राहुल गांधी के मुताबिक, इस समय दुनिया में दो बड़े डेटा पूल हैं भारत और चीन। ऐसे में भारत के पास वैश्विक शक्ति बनने का सुनहरा अवसर है। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया अब एक या दो सुपरपावर के दौर से आगे बढ़कर बहु–ध्रुवीय (डनसजप–चवसंत) व्यवस्था की ओर जा रही है। उन्होंने अमेरिकी वर्चस्व और डॉलर की स्थिति को चुनौती मिलते हुए बताया। उनका कहना था कि एआई के इस दौर में पारंपरिक आईटी इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा और कई इंजीनियरों की नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। राहुल गांधी ने हालिया अमेरिका–भारत व्यापार समझौते पर सवाल उठाते हुए ।

संपादकीय

जन समस्याओं का हल सांत्वना का भ्रम

सालाना बजट आज महज वित्तीय विवरण, कर दरों में हेरफेर, खर्च के लक्ष्यों की घोषणा और जहां–तहां कुछ प्रोत्साहनों के एलान का दस्तावेज भर रह गया है। बुनियादी आर्थिक समस्याओं के हल की बात उसके दायरे से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस की राय में केंद्रीय बजट अर्थव्यवस्था की बुनियादी चुनौतियों से आंख मिलाने में नाकाम रहा। दरअसल, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तो यहां तक कहा कि वित्त मंत्री ने उन चुनौतियों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। मसलन, अमेरिकी टैरिफ से कारखाना उत्पादकों और निर्यातकों के सामने आई चुनौतियों, व्यापार घाटे, निम्न ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एफडीआई की अनिश्चितता, राजकोषीय सेहत में सुधार की धीमी गति, महंगाई के सरकारी आंकड़ों एवं अनुभवजन्य स्थिति में फर्क, लाखों एमएसएमई इकाइयों के बंद होने, बेरोजगारी, और शहरी बुनियादी ढांचे में लगातार गिरावट पर निर्मला सीतारमन ने चुप्पी साध ली। ये आलोचना वाजिब है। यह हकीकत है कि आज सालाना बजट महज वित्तीय विवरण, कर दरों में हेरफेर, खर्च के लक्ष्यों की घोषणा और जहां–तहां कुछ प्रोत्साहनों के एलान का दस्तावेज भर रह गया है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जब असल में मोनोपॉली पूंजीवाद का रूप ले चुकी हो, तो बिना उस ढांचे को चुनौती दिए सरकारें अक्सर ढांचागत समस्याओं का हल निकालने में अक्षम हो जाती हैं। नतीजतन, बजट के जरिए शायद ही बाजार में मांग और निजी निवेश की स्थितियां बनाई जा सकती हैं। बिना ऐसा हुए ना तो रोजगार सृजन संभव है, और ना ही मानव विकास या रहन–सहन की बेहतर सूरत बनाना। देसी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं नहीं होगी, तो भारतीय उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में टिकने की बात महज एक खामख्याली ही है। बाकी जहां तक व्यापार घाटा, पर्याप्त मात्रा में एफडीआई ना आना या पोर्टफोलियो इन्वेस्टरों के भारत से पैसा निकालने, या रुपये की कीमत मे गिरावट की बात है, तो वे जारी हालात के नतीजे हैं। यथार्थ तो यह है कि लगातार अपनी ताकत कॉरपोरेट सेक्टर को ट्रांसफर करती गई सरकार की अब ऐसे मसलों का हल ढूंढने की काबिलियत अब काफी हद तक क्षीण हो चुकी है। इस हाल में आबादी के कुछ समूहों को नकदी हस्तांतरण कर चुनावी लाभ की योजनाएं शुरू करने से आगे कुछ करने को वह सोच नहीं पाती। उन योजनाओं के जरिए जन समस्याओं का हल करने की सांत्वना का भ्रम वह पैदा करती है। इस बार भी वह इतना ही कर पाई।

भाजपा में श्नबीन युग की शुरुआत

अजीत द्विवेदी

भारतीय जनता पार्टी के 12वें अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की नियुक्ति हो गई है। भाजपा ने संगठन पर्व मना कर उनको अध्यक्ष के पद पर आसीन किया। पिछले महीने 14 दिसंबर को जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उस समय से यह चर्चा चल रही है भाजपा में ये श्नबीन युगच्य की शुरुआत है। यह एक वर्ड प्ले की तरह है। यहां नए अध्यक्ष के नाम के साथ एक नए युग की शुरुआत का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या भाजपा में सचमुच नए अध्यक्ष के साथ नए युग की शुरुआत होगी और दूसरा सवाल यह है कि क्या सचमुच भाजपा का जो अध्यक्ष होता है उसका कोई युग होता है? भाजपा के अब तक 11 अध्यक्ष हुए हैं लेकिन सबके कार्यकाल को उसके युग के तौर पर नहीं देखा जाता है। 45 साल पहले जब भाजपा बनी तब से मोटे तौर पर दो ही युग रहे। एक अटल–आडवाणी का युग था और अब मोदी–शाह का युग है। बाकी इनके बीच संक्रमण का काल रहा है। सो, भाजपा में यह मोदी–शाह के युग की ही निरंतरता है। हां, उसमें नितिन नबीन को अपने आप को साबित करना है। उनका कार्यकाल इस बात से साबित होगा कि वे आगे बढ़ कर कितनी चुनौतियां स्वीकार करते हैं और उसको पूरा करने में किस तरह की भूमिका निभाते हैं। निश्चत रूप से नए अध्यक्ष का चुनाव भाजपा के नए दौर की या नए युग की शुरुआत नहीं है, बल्कि मोदी–शाह युग की निरंतरता है। इसलिए संगठन का कामकाज पहले की तरह ही चलता रहेगा। फिर भी नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का एक बड़ा संदेश आगे की राजनीति के लिए है। भाजपा ने दिखाया है कि वह आगे की राजनीति के लिए किसी तरह का प्रयोग करने का जोखिम उठाने को तैयार रहती है। यह मामूली फैसला नहीं था कि, जिस नेता के पास संगठन का सामान्य से ज्यादा कोई अनुभव न हो, जिसने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में कोई भूमिका नहीं निभाई हो और अपने राज्य में भी अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर की राजनीति में बहुत सीमित काम किया हो उसको सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। भाजपा ने यह किया तो इसका एक बड़ा संदेश भाजपा के नेताओं के लिए था तो साथ साथ राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के लिए भी था। याद करें कि पिछले तीन साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कितने तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जून 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होकर 240 पर आने के बाद कैसे कहा जा रहा था कि अब राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ तय करेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। संघ की पसंद के तौर पर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के नाम की चर्चा हो रही थी। मोदी और शाह की पसंद के तौर पर भी आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन न तो जिनको संघ की पसंद बनाया जा रहा था वे अध्यक्ष बने और न जो बड़े अनुभवी और संगठन से जुड़े नेता थे वे बने। तभी नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम वाला फैसला भी है। नितिन नबीन से ज्यादा चुनौती मोदी और शाह की इसलिए है क्योंकि आगे के चुनाव नतीजों और संगठन के कामकाज के लिए जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आयद होगी। इस साल पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनकी सफलता और विफलता का आकलन नितिन नबीन के कामकाज से नहीं होगा। भाजपा जीतती है तो उसका श्रेय जरूर नितिन नबीन को भी मिल सकता है लेकिन हार का ठीकरा उनके ऊपर नहीं फूटेगा। न तो विपक्ष उनको जिम्मेदार ठहराएगा और न भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उनको जिम्मेदार मानेंगे। संगठन के मामले में मोदी और शाह के अब तक के ज्यादातर फैसले मास्टरस्ट्रोक साबित होते रहे हैं या यूं कहें कि लगातार चुनावी कामयाबी मिल रही है इसलिए संगठन में किसको कहां बैठाया गया यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। यह बात मोटे तौर पर पार्टी संगठन के पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों और भाजपा शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के बारे में भी सही है। क्योंकि हर जगह चुनाव मोदी और शाह ही लड़ते दिखते हैं। आने वाले दिनों में भाजपा की इस राजनीति की निरंतरता बनी रहेगी। अब जो काम जेपी नड्डा करते थे वह काम नितिन नबीन करेंगे। गुणात्मक रूप से कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है। प्रतीकात्मक रूप से कुछ संदेश जरूर जाएंगे। जैसे एक संदेश अगड़ी जाति के नेता को अध्यक्ष बनाने का है। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी अगड़ा अध्यक्ष चुनती रही है। नितिन नबीन का चुना जाना उस नीति की भी निरंतरता है। नितिन नबीन के जरिए इसका संदेश पूरे देश में होगा। एक प्रतीकात्मक संदेश पश्चिम बंगाल में भी होगा, जहां ब्राह्मण और कायस्थ भद्रलोक पहले लेफ्ट का समर्थक था और अब ममता बनर्जी का समर्थक है। नितिन नबीन के जरिए दूसरा संदेश युवाओं का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अध्यक्ष चुने के बाद के भाषण में कहा कि नितिन नबीन मिलेनियल युवा हैं। उनका जन्म उस साल हुआ था, जिस साल भाजपा का गठन हुआ था। यानी भाजपा के साथ ही 1980 में उनका जन्म हुआ।

युएनएससी में भारत के दावे का किया समर्थन, व्यापार समझौता करने को भी तैयार

नीरज

भारत और चीन के बीच रिश्तों की जमी बर्फ अब पिघलने लगी है और यह बदलाव केवल सीमा तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि व्यापार, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन तक फैलता नजर आ रहा है। नई दिल्ली में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओशु के बीच हुई सामरिक संवाद बैठक ने यह साफ कर दिया कि दोनों देश टकराव की लंबी थकान के बाद अब ठोस लाभ की राह तलाश रहे हैं। बातचीत का मुख्य आधार रहा व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखना। हम आपको याद दिला दें कि करीब 4 वर्ष तक चले पूर्वी लद्दाख गतिरोध ा ने दोनों देशों के संबंधों को झकझोर दिया था। उसके बाद हुए सीमा समझौते और शीर्ष नेतृत्व की बैठकों के फल अब सामने आने लगे हैं। दोनों पक्षों ने माना कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता ही व्यापक रिश्तों की बुनियाद है। इसी सोच के साथ द्विपक्षीय व्यापार से जुड़ी अड़चनों को राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से सुलझाने पर जोर दिया गया। बैठक में वायु सेवा समझौते को जल्द नया रूप देने, जन से जन संपर्क बढ़ाने और प्रवेश अनुमति पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को भरोसे की बहाली का संकेत माना गया और इसके दायरे को आगे बढ़ाने की आशा जताई गई। सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात रही चीन का यह कहना कि वह भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की आकांक्षा को समझता और उसका सम्मान करता है। यह रुख पहले के ठंडे या विरोधी रवैये से अलग माना जा रहा है। सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं और हर एक के पास वीटो शक्ति है। ऐसे में किसी नए स्थायी सदस्य के रास्ते में इन पांचों की सहमति निर्णायक होती है। पहले चार स्थायी सदस्यों ने अलग अलग समय पर भारत के दावे का समर्थन जताया है, जबकि चीन का रुख अस्पष्ट या ठंडा रहा। अब बीजिंग की यह नरमी नई चर्चा को जन्म दे रही है। चीन ने यह भी कहा कि बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति में दोनों देशों को प्रतिद्वंद्वी नहीं, सहयोगी साझेदार के रूप में देखना चाहिए। दोनों ने बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, ग्लोबल साउथ की एकजुटता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात दोहराई। साथ ही भारत की इस वर्ष की ब्रिक्स अध्यक्षता और भारत में होने वाली ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए चीन ने समर्थन जताया। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते आगे बढ़ाए हैं और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविध बना रहा है। ऐसे में चीन का भारत की ओर व्यापार और कूटनीति का हाथ बढ़ाना केवल सद्भाव नहीं, बल्कि रणनीति भी माना जा रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं यदि टकराव कम कर सहयोग बढ़ाती हैं, तो एशिया ही नहीं, पूरे विश्व का शक्ति गणित बदल सकती हैं। पिछले छह महीनों में भारत चीन संबंधों में जो सुधार दिखा है, उसमें शीर्ष नेतृत्व की मुलाकातें, सैन्य स्तर पर संवाद और आर्थिक संपर्क की बहाली शामिल है। हालांकि अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर संवाद की पटरी पर लौटना अपने आप में बड़ा बदलाव है। देखा जाये तो भारत चीन रिश्तों में यह नरमी केवल दोस्ती की कहानी नहीं, बल्कि कठोर यथार्थ की राजनीति है। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते व्यापार और सामरिक समीकरण ने बीजिंग को संकेत दिया है कि नई दिल्ली अब विकल्पों से भरपूर है। ऐसे में चीन का लहजा बदलना स्वाभाविक भी है और मजबूरी भी। वह नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह पश्चिमी खेमे की ओर झुक जाए और एशिया में उसके लिए संतुलन बिगड़ जाए। भारत के लिए भी यह मौका है, पर खतरे से खाली नहीं। चीन के शब्द मधुर हो सकते हैं, पर उसकी नीति हमेशा अपने हित के इर्द गिर्द घूमती है। सीमा पर शांति की बात स्वागत योग्य है, पर जमीन पर सख्त चौकसी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। इतिहास बताता है कि भरोसा और सतर्कता दोनों साथ साथ चलाने

पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर चीन का नरम संकेत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना सुधार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन केवल समझने और सम्मान करने से काम नहीं चलेगा, खुला और स्पष्ट समर्थन ही असली कसौटी होगा। बहरहाल, यदि भारत और चीन सच में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित कर सहयोग का रास्ता निकाल लेते हैं, तो इसके वैश्विक और क्षेत्रीय भूराजनीतिक निहितार्थ गहरे होंगे। एशिया में तनाव घट सकता है, आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थिर हो सकती हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हो सकती है। इससे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को भी नया बल मिलेगा, जहां पश्चिम का वर्चस्व अकेला निर्णायक न रहे। पर अंतिम सवाल यही है कि क्या यह बदलाव स्थायी होगा या हालात बदलते ही फिर तल्खी लौट आएगी। भारत को इस नए दौर में आत्मविश्वास, आर्थिक शक्ति और सैन्य तैयारी के साथ कदम बढ़ाना होगा। दोस्ती की मेज पर हाथ मिलाते समय भी सीमा पर नजर और दिमाग, दोनों खुले रखने होंगे। यही परिपक्व शक्ति की पहचान है।

कृषि उपज के लिए बाजार को खोलना यानी बवंडर को निमंत्रण

उमेश

इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बरसों से भारतीय कृषि बाजार में बड़ी और व्यापक पहुंच हासिल करने की कोशिश में है। हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है। इसके तहत अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान 18 प्रतिशत के ही टैरिफ पर उपलब्ध हो सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामानों पर मनमाने तरीके से थोपे गए पचास प्रतिशत के टैरिफ के मुकाबले मौजूदा व्यापार समझौते के तहत अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 18 प्रतिशत का टैरिफ कम ही कहा जाएगा। हालांकि अतीत के करीब तीन प्रतिशत के मुकाबले फिर भी यह बहुत ज्यादा है। बहरहाल इसी समझौते के मद्देनजर जिस तरह से अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक लेस्ली रोलिंग्स ने खुशी जताई, उससे भारतीय किसान आशंकित हो उठे। भारतीय किसानों के आशंकित होने की वजह रोलिंग्स का बयान ही नहीं, अमेरिकी कृषि विभाग की कोशिशें भी हैं। रोलिंग्स ने व्यापार समझौते पर तीन फरवरी को एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने में मदद करेगा, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। इससे ग्रामीण अमेरिका में नकदी आएगी। रोलिंग्स यहीं पर नहीं रूके। उन्होंने सिर्फ 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि भारत के साथ कृषि कारोबार के चलते अमेरिका को 1.3 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है। रोलिंग्स ने उम्मीद जताई कि नए व्यापार समझौते की वजह से विशाल आबादी वाला भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार हो सकता है। रोलिंग्स की इस खुशी की वजह से भारतीय किसानों का आशंकित होना जायज है। अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा पचास अरब डॉलर है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत अपने कृषि बाजारों को खोले। भारत की चिंता की वजह उसकी खेती–किसानी वाली बड़ी जनसंख्या है। भारत के छियासी प्रतिशत किसान सीमांत या लघु हैं। जिनकी जोत दो हेक्टेयर से कम है। भारत में खेती पर करीब 10.7 करोड़ परिवार निर्भर हैं। यह जनसंख्या का करीब बासठ प्रतिशत है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में घुसने की अनुमति मिलती है तो भारी सब्सिडी के चलते भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है। इससे भारतीय किसानों के सामने संकट उठ खड़ा हो सकता है। किसानों की आशंकाओं को विपक्षी दलों ने अपने ऊंचे सुरों से और बढ़ाया ही है। लेकिन कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि भारत–अमेरिकी व्यापार समझौते में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। चौहान का यह भी कहना है कि इस कारोबारी समझौते से देश के मुख्य खाद्यान्नों, मिलेट्स, फलों,सब्जियों और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह अलग रखा गया है। इस लिहाज से देखें तो इस कारोबार समझौते से देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, इस समझौते से भारतीय किसानों को नए अवसर मिलेंगे,क्योंकि इस समझौते में कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत की ओर से अमेरिका समेत कई देशों को करीब 63 हजार करोड़ के चावल का निर्यात कर चुका है। भारत सरकार का दावा है कि नए टैरिफ समझौते से भारतीय किसानों के चावल और मसालों के साथ ही टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा। भारत–अमेरिकी समझौते के तहत भारत को अमेरिका से पांच सौ अरब डॉलर का सामान पांच सालों में खरीदना है। वैसे समझौते पर जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है, उसके तहत भारतीय कृषि बाजार को भी खोलने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस समझौते से, भारतीय चावल, गेहूं, सोया और मक्का जैसे अनाजों को बाहर रखा गया है और साथ ही ट्रेड डील से चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बाहर हैं। ऐसा करने की वजह यह है कि भारतीय किसान और डेयरी उद्योग को कारोबारी परेशानियां न झेलनीं पड़ें। वैसे भी भारत लंबे समय से कृषि और डेयरी उद्योग को 'रेड–लाइन' यानी किनारे रखने वाला सेक्टर मानता रहा है। इसकी वजह है कि गांवों में इनसे जुड़े काफी रोजगार हैं। इन सेक्टर को खोलने को लेकर भारत की बातचीत यूरोप और ब्रिटेन से भी अटक चुकी है। ऐसे में अमेरिका के लिए इस बाजार को खोलना भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक तो होगा ही, राजनीतिक बवंडर की वजह भी बन सकता है। इस बवंडर का सामना करने की हिम्मत विरली राजनीतिक ताकतें ही कर सकती हैं। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, खासतौर पर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए तीन लाख अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा बाजार खुलने की उम्मीद है। इसकी वजह से जो निर्यात बढ़ेगा, उससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। भारत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, दूध, पनीर, एथनॉल, तंबाकू, सब्जियां और मांस सहित संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों को पूर्ण रूप से संरक्षित करेगा। दोनों देश अपने–अपने हित वाले क्षेत्रों में एक–दूसरे को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में भारत ने अमेरिका से 2.4 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद आयात किए थे, जिनमें ज्यादातर ताजे फल, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट मादक पेय, कच्चा कपास, वनस्पति तेल और प्रोसेस्ड सामान हैं। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को 6.2 अरब डॉलर का कृषि निर्यात किया, जिनमें समुद्री उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, चावल, जड़ी–बूटियों के आयुर्वेदिक उत्पाद प्रमुख रहे। यह भारत के कुल 53.2 अरब डॉलर सालाना के कृषि निर्यात का 11.74 प्रतिशत है। कृषि और डेयरी उत्पाद के कारोबार के इसी असुंलन की वजह से अमेरिका भारतीय बाजार में घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सूत्र इससे साफ इनकार कर रहे हैं। भारत के सामने संकट यह है कि अगर उसने इस क्षेत्र को खोला तो छोटे और सीमांत किसानों के सामने जो चुनौतियां खड़ी होंगी, उनसे वह कैसे निबट पाएगा।

मोदी–शाह के दौरों के बावजूद भगवा पार्टी का मनोबल अधिक मजबूत नहीं हुआ

तीर्थंकर

भगवा खेमे का हिंदू वोटों का समीकरण सही नहीं है। हो सकता है कि समुदाय सत्ताधारी सरकार से खुश न हो, लेकिन इसके भाजपा को एक साथ वोट देने की उम्मीद कम है। हालांकि विपक्ष के नेता, शुभेंदु अधिकारी अब तक के सबसे लोकप्रिय और दिखने वाले भाजपा नेता हैं, लेकिन उनके अपने खेमे में भी उनके विरोधी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हराने की बात कहना भाजपा के लिए जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, भले ही भाजपा नेता इस साल अप्रैल–मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने की बात कर रहे हों। पूरी कोशिश करने के बावजूद लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद, भगवा पार्टी की 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीदें सत्ता विरोधी भावना, पूरे बंगाल में हिंदू एकजुटता, और टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली कहानी पर टिकी हैं। इन मुद्दों के आधार पर, इस चुनावी राज्य में भाजपा का प्रचार टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करिश्मे और उनकी सरकार के उन लोकप्रिय परियोजनाओं के खिलाफ होगा, जिनसे उन्हें चुनावी फायदा हुआ था। टीएमसी के इन चुनावी प्लेटफॉर्म से पार पाना भगवा खेमे के लिए अब तक की सबसे मुश्किल चुनावी परीक्षा होगी।टीएमसी नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना भाजपा के लिए सबसे अच्छा दांव लगता है क्योंकि वह चुनाव प्रचार शुरू करने वाली है। रुपये के बदले नौकरी देने का आरोप और टीएमसी के पूर्व महासचिव और शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के साथी के घर से मिले नकदी के बंडल और आरजीकार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक लेडी डॉक्टर के बलात्कार और उसकी हत्या ने टीएमसी नेतृत्व को मुश्किल में डाल दिया है।इसके साथ ही, भगवा खेमे की नजर सत्ताविरोधी कारक और हिंदू वोटों के एकजुट होने पर है। सत्ताविरोधी कारक इसलिए बेअसर है क्योंकि राज्य के भगवा खेमे के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जा सके। भगवा खेमे का हिंदू वोटों का समीकरण सही नहीं है। हो सकता है कि समुदाय सत्ताधारी सरकार से खुश न हो, लेकिन इसके भाजपा को एक साथ वोट देने की उम्मीद कम है। हालांकि विपक्ष के नेता, शुभेंदु अधिकारी अब तक के सबसे लोकप्रिय और दिखने वाले भाजपा नेता हैं, लेकिन उनके अपने खेमे में भी उनके विरोधी हैं। राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया है कि वे तब से भाजपा में हैं जब शुभेंदु तृणमूल में थे और ममता बनर्जी के खास सिपहसालार थे।इसके अलावा, टीएमसी संगठन के मामले में भाजपा से बहुत आगे है। तृणमूल के सांगठनिक नेटवर्क ने पार्टी को संभाला, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी राज्य में आए हों और चुनावी माहौल को और गरमाया हो। हालात ऐसे हो गए हैं कि भगवा खेमा अपनी सांगठनिक कमजोरी को ठीक करने के लिए राज्य से किसी नेता को नहीं ला सका। इसने पिछले सितंबर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी चुना और उन्हें पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने का काम सौंपा।केंद्रीय नेतृत्व के इस आदमी ने पार्टी के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन राज्य के भगवा खेमे के सूत्रों ने बताया कि यादव को उन्हें दिए गए काम के लिए समय काफी नहीं लगा। सूत्रों ने बताया कि राज्य भाजपा के पास बूथ लेवल के इतने कार्यकर्ता नहीं हैं जिनकी मौजूदगी या गैरमौजूदगी मतदान के दिन किसी उम्मीदवार की जीत या हार तय कर सके। अगर ये कार्यकर्ता 2021 के विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन बाहर रहते तो भगवा खेमे में विधायकों की संख्या और ज्यादा होती।इस बीच, तृणमूल प्रमुख अपनी 2021 की रणनीति को जारी रखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को श्बाहरीश्य कहती रही हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) की पृष्ठभूमि में, पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय कोई भी श्बाहरीश का टैग नहीं लगवाना चाहता। गुमशुदा लोगों ने पहले ही भाजपा के विधायकों की संख्या कम कर दी है। ममता बनर्जी का करिश्मा और टीएमसी की लगातार तीन जीत आने वाले चुनावों में भगवा खेमे के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए बहुत से लोगों को उत्सुक नहीं करेंगी। एसआईआर को लेकर चिंता और मतुआ समुदाय में भाजपा नेतृत्व में फूट आने से आने वाले चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके भाई, भाजपा विधायक सुब्रत ठाकुर के बीच सार्वजनिक रूप से झगड़ा हुआ है। मतुआ पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में फैला एक दलित धार्मिक ग्रुप है, जिसके भारी समर्थन की वजह से 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को शानदार नतीजे मिले थे। वे भगवा खेमे और उसके कार्यनिष्पादन की मजबूती रहे हैं, हालांकि इस बात पर शक है कि इसे दोहराया जा सकेगा। भगवा खेमे के लोकप्रिय नेता बहुत ज्यादा अगर–मगर पर निर्भर लग रहे हैं। राज्य भाजपा के कुछ बड़े नेताओं को लगता है कि कई मुस्लिम ग्रुप टीएमसी की नाकामी से नाखुश हैं, जो उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की लिस्ट से बाहर होने से नहीं रोक पाई, इस बार भाजपा को

वोट देंगे। लेकिन इस सोच के चक्कर में, इन नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के कई वर्गों को श्बाहरीश और श्घुसपैठिएश बताने की अपनी ही बात को नजरंदाज कर दिया है। अगर ये अल्पसंख्यक वर्ग के एक विशेष खेमे के लोग अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल भी लेते हैं, तो भगवा खेमा आखिरी पार्टी होगी जिसे वे वोट देंगे। इन अल्पसंख्यक खेमों को वर्तमान में चल रही एसआईआर अभियान के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर होने का डर है। भाजपा के साथ अपने पिछले अनुभव को देखते हुए, उन्हें लगता है कि भगवा पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन्हें कम अहमियत मिलेगी। एसआईआर अभ्यास के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान करने के आरोप लगाने के बाद टीएमसी प्रमुख पर नाटक करने का आरोप लगा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की जनता के हित में उनकी बहस ने उनके मतदाताओं के लिए एक संदेश दिया है, जो शायद उनके मतदान करने के तरीके में दिखेगा। महिलाओं की भलाई की योजनाओं में खर्च बढ़ाने के बाद ममता बनर्जी सरकार का संदेश सहयोग देने का है। महिलाओं पर केंद्रित नकद लाभ देने की योजना में बढ़ोतरी पाने वाली महिला मतदाताओं के अपने हितैषी टीएमसी के खिलाफ वोट करने की संभावना कम है। यह बात भाजपा नेता भी अकेले में मानते हैं। भाजपा आलाकमान पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची पर विचारण कर रहा है। आखिरी तस्वीर इस महीने के आखिरी हफ्ते में ही सामने आएगी। एक बार उम्मीदवारों के नाम आधिकारिक तौर पर घोषित हो जाने के बाद भाजपा पूरे जोर–शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर देगी।

जलशक्तिमंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की सिंचाई एवं जल संसाधन परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा

लखनऊ, (संवाददाता)। दिनांक 10 फरवरी 2026।उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्यालय स्थित सभागार में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सहित विभिन्न संगठनों के मुख्य अभियंता (सिविलध्यांत्रिक) स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक के दौरान जलशक्ति मंत्री ने विभाग की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। धीमी प्रगति वाली परियोजनाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य संस्कृति में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना की अनिवार्य रूप से मासिक मॉनिटरिंग की जाए, बाधाओं की पहचान कर उन्हें तत्काल दूर किया जाए तथा कार्यों की गुणवत्ता, समय–सीमा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। गुणवत्ता अथवा समय–सीमा में चूक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।श्री स्वतंत्र देव सिंह ने निर्देश दिए कि विभाग की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए, जिससे योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों एवं आम नागरिकों तक समय से पहुंच सके। उन्होंने विभागीय व्यय की समीक्षा करते हुए स्वीकृत बजट के समयबद्ध, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख उपयोग पर विशेष बल दिया। साथ ही उन्होंने आजादी से पूर्व स्थापित नलकूपों को धरोहर नलकूप के रूप में संरक्षित करने के निर्देश भी दिए।बैठक में बाढ़, सिंचाई एवं यांत्रिक क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। विशेष रूप से वृंदावन–मथुरा स्थित नदी घाटों के विस्तार, नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण परियोजना की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों में पूर्ण होने वाली नौ प्रमुख परियोजनाओं, जिनमें मध्यगंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण), एरच बहुद्देशीय बांध परियोजना, किच्छा बैराज परियोजना, रामपुर बैराज परियोजना, रोहिन नदी परियोजना तथा महाराजगंज जनपद में रोहिन बैराज–3 शामिल हैं।

घर पहुंचा संदिग्ध आतंकी अब्दुल का शव

लखनऊ, (संवाददाता)। राम मंदिर पर हमले की साजिश में आरोपी संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान का शव लेकर परिजन बुधवार सुबह सात बजे मजनाई गांव पहुंचे। शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। रविवार की रात फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद ग्रेनेड व डेटोनेटर के साथ पकड़े गए राम मंदिर पर हमले की साजिश के आरोपी संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की साथी कैदी अरुण चौधरी ने हत्या कर दी थी। सोमवार को उसके पिता अबू बकर व चाचा उस्मान शव लाने फरीदाबाद गए थे। बुधवार सुबह सात बजे दोनो एम्बुलेंस से शव लेकर पैतृक फव मजनाई गांव पहुंचे।जहां परिजनों के साथ रिश्तेदारों, सगे संबंधियों व लोग पहले से ही मौजूद थे।शव के पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।परिजन चीखने चिल्लाने लगे। शव को दफन करने की सभी तैयारियां पहले से ही गांव के समीप स्थित कब्रिस्तान में की गई थी। परिजनों व नाते रिस्तेदारों के अंतिम दीदार के पश्चात शव को गांव में ही स्थित रहबरे इस्लामिया मदरसे में ले जाया गया जहां जनाजे की नमाज इमाम अब्दुल मजीद द्वारा पढ़ाई गई।उसके बाद जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा और करीब आठ बजे शब को सुपुर्दे खाक किया गया।इस दौरान क्षेत्रधिकारी मिल्कीपुर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस फोर्स तैनात रही।

संक्षिप्त खबरें

शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव है वार्षिकोत्सव

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विवि परिसर में मंगलवार से शैक्षणिक सत्र 2025–26 की वार्षिक उत्सव की शुरुआत हुई। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, वार्षिक शैक्षणिक एवं खेल प्रतियोगिताएं हुईं। 13 फरवरी तक होने वाले संस्कृत सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा एवं स्वामी विवेकानंद जयंती में प्रतिभाग करने वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। परिसर निदेशक प्रो. सर्वनारायण झा ने कहा कि वार्षिकोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, संस्कारों और शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव है।

एक दिन में बदली 425 युवाओं की तकदीर

लखनऊ, (संवाददाता)। साक्षात्कार खत्म होते ही जब हाथ में नियुक्ति पत्र थमाया गया तो युवाओं की आंखों में सपनों की चमक साफ नजर आई। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को आयोजित रोजगार मेले में युवाओं के लिए नौकरी के कई दरवाजे खुले। कुल 1500 पदों के सापेक्ष 1300 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कर प्रतिभाग किया, जिनमें से 425 युवाओं का चयन कर मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए गए। चयनित अभ्यर्थियों को 3 लाख से 5.5 लाख रुपये वार्षिक वेतन पैकेज पर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग के सहयोग से आयोजित इस मेले में टाटा मोटर्स, फ्लिपकार्ट, एचसीएल, आईसीआईसीआई बैंक सहित 21 प्रमुख निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कुल 1227 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए। लखनऊ के साथ–साथ हरदोई, लखीमपुर, उन्नाव, सीतापुर, कानपुर, मेरठ और

नोएडा समेत कई जिलों से आए युवाओं ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने किया। सेवायोजन विभाग के अपर निदेशक सूर्यकांत कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की पहल से युवाओं को घर के नजदीक रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे पलायन भी कम होगा। प्रोमोटर, असिस्टेंट मैनेजर, एटीएम ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिस्ट और तकनीकी सहायक जैसे पदों पर नियुक्तियां की गईं। तीन कंपनियों ने इंटरव्यू के बाद ऑफर दिया। जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रही हूं, वहीं से नौकरी मिली। इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए। उम्मीद कम थी, लेकिन चयन हो गया। कोशिश रहेगी कि पढ़ाई प्रभावित न हो और नौकरी में भी बेहतर प्रदर्शन करूं। रजिस्ट्रेशन कराया है, कुछ कंपनियों ने बायोडाटा लिया है।

ट्रेनें बढ़ीं पर जीआरपीकर्मी नहीं, जिलों से मांगे गए 2740 पुलिसकर्मी अब निकाला गया यह विशेष रास्ता

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में ट्रेनों और यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है लेकिन बीते 28 वर्ष से जीआरपी कर्मियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत अब कमिश्नरेट और जिलों में तैनात 2740 कर्मियों को जीआरपी में एक वर्ष के लिए विशेष ड्यूटी पर तैनात करने का फैसला लिया गया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन कर्मियों को उनके गृह जिले के जीआरपी थानों में तैनात किया जाएगा। इनमें महिला कर्मी भी शामिल होंगी। वर्तमान में जीआरपी में वर्ष 1998 से डीजी से लेकर सिपाही तक कुल 6000 अफसर और कर्मचारियों की जनशक्ति (नियतन) है। इसमें अब तक करीब 28 वर्ष से कोई इजाफा नहीं हुआ है। कई बार रेल मंत्रालय को जनशक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। इस दौरान प्रदेश में ट्रेनों की संख्या बढ़कर 3050 और यात्रियों की संख्या रोजाना 30 लाख तक हो गई है। ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब दूसरा रास्ता निकाला गया है। कमिश्नरेट और जिलों में तैनात इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही रैंक के 2740 कर्मियों को अब एक वर्ष के लिए जीआरपी में भेजा जाएगा। उनकी तनख्वाह उनके कमिश्नरेट और जिले से ही जारी होगी। बाद में उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। यह वर्तमान में जीआरपी में तीन साल के लिए नागरिक पुलिस के कर्मियों की तैनाती की प्रचलित व्यवस्था से अलग होगा। दरअसल, जीआरपी कर्मियों की आधी तनख्वाह रेल मंत्रालय वहन करता है। यूपी पुलिस द्वारा जीआरपी कर्मियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय द्वारा बार–बार ठुकरा देता है।

विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरक्षण नीति पर सरकार का पक्ष रखा

लखनऊ, (संवाददाता)। वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं में लागू आरक्षण नीति पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ लागू करने के अपने संकल्प को दोहराती है।उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 40 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है और आरक्षित वर्ग का कोई भी पात्र अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है।श्री मौर्य ने बताया कि सभी सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा 30 दिसंबर 2025 को शासनादेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भ्रम या अनियमितता न हो और सभी वर्गों को उनका संवैधानिक अधिकार मिले।लेखपाल भर्ती का उल्लेख करते हुए उप मुख्यमंत्री ने 7,994 पदों का विस्तृत विवरण सदन के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इनमें 3,205 पद अनारक्षित, 1,679 पद अनुसूचित जाति, 160 पद अनुसूचित जनजाति, 2,158 पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 792 पद आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में हुई त्रुटि का सुधार करा दिया गया है और आरक्षण व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती माफिया पर सख्ती से कार्रवाई करने, पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं को लागू करने और आरक्षण व्यवस्था को हर हाल मेंसुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

संक्षिप्त खबरें

राम की नगरी में आने वाले भक्तों का स्वागत करेगा लक्ष्मण द्वार,पिंक सश्लिड स्टोन से सजेगा प्रवेश द्वारा

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।राम की नगरी अब भक्तों के लिए और अधिक आकर्षक व स्वागतमय बन रही है।राम मंदिर के दर्शनार्थ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत करने के लिए एनएच–330ए (अयोध्या–गोण्डा मार्ग) पर एक शानदार लक्ष्मण द्वार का निर्माण तेजी से चल रहा है।यह प्रवेश द्वार अयोध्या की धार्मिक गरिमा को और निखारने के साथ–साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।यह भव्य लक्ष्मण द्वार देईपुरध्कटरा भागचंद्र' अहतमाली क्षेत्र में 40 मीटर चौड़े मार्ग पर बनाया जा रहा है।उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को इस परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी गई है।कुल निर्माण लागत 3,970.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।द्वार को पिंक सॉलिड स्टोन से सजाया जाएगा, जो इसे राजसी एवं आकर्षक बनाएगा। पिंक स्टोन का उपयोग न केवल सौंदर्य बढ़ाएगा, बल्कि यह स्थानीय शिल्प कौशल को भी प्रदर्शित करेगा और अयोध्या की प्राचीन वास्तुकला से प्रेरित होगा। राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र यादव ने बताया कि वर्तमान में परियोजना का 35 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अक्टूबर तक पूरा लक्ष्मण द्वार तैयार हो जाएगा।लक्ष्मण द्वार के बनने से यह मार्ग धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक भी बन जाएगा। रामायण काल में लक्ष्मण जी के भाई राम के प्रति समर्पण की याद दिलाता यह द्वार भक्तों के मन में श्रद्धा एवं उत्साह का संचार करेगा। अयोध्या विकास की इस नई परियोजना से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का धार्मिक पर्यटन नक्शा और चमकदार हो रहा है।सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में धार्मिक स्थलों का विकास एवं पर्यटन संवर्धन प्रमुख स्थान रखता है। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद यहां पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लक्ष्मण द्वार का निर्माण इसी दिशा में एक और कदम है, जो न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। स्थानीय व्यापारियों, होटलों, परिवहन सेवाओं और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। एनएच–330ए पर यह लक्ष्मण द्वार अयोध्या–गोण्डा मार्ग की गरिमा को कई गुना बढ़ा देगा।

रोजगार के लिए अंग्रेजी व कंप्यूटर भी सीखें मुस्लिम युवा : अंसारी

लखनऊ, (संवाददाता)। अल्पसंख्यक समाज के युवाओं के लिए भाषा शिक्षा को रोजगार से जोड़ना वक्त की जरूरत है। अरबी के साथ अगर अंग्रेजी, कंप्यूटर और तकनीकी कौशल भी सीखे जाएं तो युवाओं के लिए देश–विदेश में अवसरों के दरवाजे खुलते हैं। यह बात अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ व हज राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मंगलवार को भाषा विश्वविद्यालय में अरबी विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षा, हुनर और रोजगार के बेहतर अवसर हर वर्ग तक पहुंचें। सरकार मदरसों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा शिक्षा को आधुनिक जरूरतों से जोड़ने के लिए प्रयासरत है।

दुधवा सफारी सीजन 2026 को लेकर तैयारियां तेज, इको–टूरिज्म पर सरकार का विशेष फोकस

लखनऊ, (संवाददाता)।दुधवा सफारी सीजनद्2026 को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में इको–टूरिज्म परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में दुधवा बेल्ट को पर्यटन के लिहाज से और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दुधवा टाइगर रिजर्व के व्याख्या केंद्र को आधुनिक और बेहतर स्वरूप देने के लिए एक अहम परियोजना पर काम किया जाएगा। इसके तहत मौजूदा कैंप कार्यालय की मरम्मत के साथ नया आकर्षक रिसेप्शन ब्लॉक बनाया जाएगा। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरप्रिटेशन सेंटर, 3–डी म्यूरल और आर्ट पेंटिंग, कैंटीन, मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत पार्क में लगी पशु आकृतियों का नवीनीकरण, पर्यटकों के बैठने के लिए गार्डन बेंच, साफ–सफाई के लिए डस्टबिन और बेहतर मार्गदर्शन के लिए साइनेज लगाए जाएंगे। दीवारों पर जंगल और वन्यजीवों को दर्शाने वाली 3–डी चित्रकारी और पेंटिंग्स की जाएंगी, जिससे पर्यटकों को दुधवा की जैव विविधता और वन्य जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। दुधवा नेशनल पार्क को पर्यटन की दृष्टि से और मजबूत बनाने के लिए साइनेज, आवास तथा डिजिटल सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पलिया और दुधवा की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों पर आधुनिक और आकर्षक साइनेज लगाए जाएंगे।पर्यटन मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय की मांग को ध्यान में रखते हुए वेलनेस टूरिज्म को इको–टूरिज्म से जोड़ते हुए प्राकृतिक वातावरण के बीच योग और मेडिटेशन स्पेस भी विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में होटल, रिसॉर्ट और होम–स्टे सुविधाओं के विस्तार को भी गति दी जा रही है। अब तक 23 होम–स्टे, 2 रिसॉर्ट और 5 होटलों का पंजीकरण किया जा चुका है। पर्यटन को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन जानकारी और बुकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। यूपी पर्यटन और यूपीटीडीबी की वेबसाइट पर दुधवा टाइगर रिजर्व का अलग पेज बनाया जाएगा, जहां होटल, रिसॉर्ट और होम–स्टे से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।दुधवा क्षेत्र में पर्यटन के साथ–साथ स्थानीय थारू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी व्यापक पहल की जा रही है। पर्यटकों को पारंपरिक थारू थाली के साथ मोटे अनाज से बने पारंपरिक व्यंजन "श्री अन्न थाली" परोसी जाएगी, जिससे स्थानीय खान–पान को नई पहचान मिलेगी। पर्यटन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, चूंकि अधिकांश होम–स्टे संचालक महिलाएं हैं, उन्हें होम–स्टे संचालन, डिजिटल भुगतान, अतिथि संवाद, स्टोरी टेलिंग और आतिथ्य प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

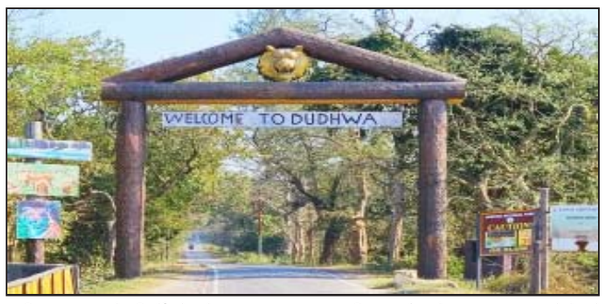

स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत महोबा में पर्यटन विकास को मिली नई गति

लखनऊ, (संवाददाता)। स्वदेश दर्शन योजना 2.0' के अंतर्गत चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी महोबा में पर्यटन विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। आल्हादृउदल की वीर गाथाओं से जुड़ी यह ऐतिहासिक धरती अब कल्चरल और एजुकेशनल टूरिज्म हब के रूप में विकसित होने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप अयोध्या, काशी और मथुरा में सफल पर्यटन विकास के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस बुंदेलखंड क्षेत्र पर केंद्रित है, ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को नई मजबूती दी जा सके।भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के निर्देश पर स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत महोबा में 24.98 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल, बांदा को जारी किया जा चुका है। परियोजना का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के माध्यम से पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है। इसमें सन इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण, त्रिकोणीय गार्डन का विकास, भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण और आधुनिक साइनेज की व्यवस्था शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट को वर्ष 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। आल्हा और उदल जैसे महान योद्धाओं की वीरता और बलिदान ने इस धरती को विशिष्ट पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी योजनाएं महोबा की ऐतिहासिक विरासत को नया जीवन दे रही हैं। वर्ष 2025 में महोबा में लगभग 28 लाख पर्यटकों का आगमन इस जिले की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। यह परियोजना न केवल पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर बनाएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को संरक्षित रखने में भी सहायक होगी।इस परियोजना का मुख्य आकर्षण सन इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसे 4,210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जा रहा है। यह केंद्र भारतीय परंपरा में सूर्य से जुड़े वैज्ञानिक महत्व और सांस्कृतिक कथाओं को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करेगा। इसकी छत का डिजाइन दिन के आठ प्रहरकृउषा, पूर्वान्ह, मध्यान्ह, अपराह्न, सायंकाल, प्रदोष, निशीथ और त्रियामाकृका प्रतीक होगा। परिसर में विशेष रूप से डिजाइन की गई सूर्यघड़ी स्थापित की जाएगी, जो सूर्य की पहली किरणों के आधार पर समय बताएगी। इसके साथ ही सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ग्रास पेवर्स और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी इको–फ्रेंडली सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे हरित और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।सन इंटरप्रिटेशन सेंटर में इंटरैक्टिव गैलरियों की श्रृंखला भी विकसित की जाएगी। इनमें एक गैलरी भारतीय परंपराओं और पश्चिमी मान्यताओं को जोड़ते हुए सूर्य और प्राचीन ग्रीक देवता हेलिओस की कथा को चित्रकारी और मूर्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करेगी। दूसरी गैलरी में कोणार्क और मार्तंड जैसे प्रमुख सूर्य मंदिरों को आर्किटेक्चरल मॉडल और विजुअल एलिमेंट्स के जरिए दर्शाया जाएगा। सूर्य और एस्ट्रोनॉमी गैलरी में मौसम, कैलेंडर और खगोलीय गतिविधियों में सूर्य की भूमिका को समझाया जाएगा, जबकि सूर्य और एस्ट्रोलॉजी गैलरी में 3डी प्रोजेक्शन और साउंड इफेक्ट्स के माध्यम से सूर्य और मानव जीवन के आपसी संबंध को रोचक ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा।परियोजना के तहत ग्रीन टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सन इंटरप्रिटेशन सेंटर से लगभग चार किलोमीटर दूर शिवतांडव रोड पर एक सुंदर त्रिकोणीय गार्डन भी विकसित किया जा रहा है। इस गार्डन के केंद्र में सात घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य देव की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसे महोबा के एक प्रमुख सांस्कृतिक लैंडमार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पर्यटकों के स्वागत के लिए तीन भव्य प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, जिन पर सैंडस्टोन से निर्मित सूर्य देव की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे महोबा की विजुअल पहचान और हेरिटेज छवि को और मजबूती मिलेगी।अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य अमृत अभिजात ने कहा कि बुंदेलखंड का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है, जिसे विशिष्ट पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत महोबा में चल रहा यह प्रोजेक्ट केवल पर्यटन सुविधाओं के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसे स्थल विकसित करना भी है, जहां विशेषकर छात्र और युवा इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व को समझ सकें। सन इंटरप्रिटेशन सेंटर जैसी पहल हेरिटेज, विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को एक साथ जोड़ते हुए एजुकेशनल और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देगी।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट पर किए हस्ताक्षर

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं, विकास की आवश्यकताओं और सुशासन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि डबल इंजन सरकार की विकासशील सोच और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतिबिंब है।वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते वर्षों में कानून–व्यवस्था, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो विश्वास स्थापित किया है, यह बजट उसी भरोसे को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि कृषि, युवा, महिला, श्रमिक और वंचित वर्गों के कल्याण के साथ–साथ पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती देने का स्पष्ट रोडमैप इस बजट में शामिल है।श्री खन्ना ने कहा कि यह बजट उन लोगों के लिए ठोस जवाब है जो उत्तर प्रदेश के विकास पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है और यह बजट उस विकास यात्रा को और गति देगा।उन्होंने बताया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए तैयार किया गया यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

सीयूजी नंबर न उठाने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी कार्यवाही - बलवंत चौधरी

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जनता की छोड़िए सर्किल पर तैनात संबंधित सीओ तथा विभिन्न थानों पर तैनात थाना प्रभारी एसपी का भी फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते।इसका उदाहरण अभी पिछले दिनों उस समय दिखाई दिया जब देर रात एक थाना क्षेत्र में एक घटना की सूचना जिला मुख्यालय पर तैनात एसपी को तो लगी।तब उन्होंने उस संबंध में संबंधित सर्किल के सीओ के सीयूजी नंबर तथा व्यक्तिगत नंबर पर देर रात फोन लगाया।लेकिन उन दोनों फोनों पर घंटी जाने के बावजूद भी उसका कोई उत्तर नहीं मिला।फिर मुख्यालय से खुद एसपी ने घटनास्थल पर जाकर बड़ी घटना होने से बचाया।नाम न छापने की शर्त पर इस बात

को खुद एसपी ने भी मानी है।वहीं पुलिस मुख्यालय पर जितने भी फरियादी अपने फरियाद को लेकर आते थे उसमें से आधे से ज्यादा समस्या सर्किल तथा थानों पर तैनात सीओ व थानाध्यक्ष द्वारा सीयूजी नंबर का नहीं उठाना रहता है। कुछ फरियादी तो अपने संबंधित थानों पर जाते तो हैं लेकिन वहां पर संबंधित थाना अध्यक्ष के न मिलने पर वहां पर तैनात पुलिसकर्मी बताते हैं कि दीवार पर अंकित सीयूजी नंबर पर बात कर ले। शिवजी नंबर पर जब बात करते हैं तो या तो फिर नॉट रीचेबल जाता है या फिर फरियादियों का मानना है की घंटी जाने के बावजूद भी थानाध्यक्ष फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते।जिसके चलते मजबूरी में फरियादियों को अपनी समस्या के लिए पैसा तथा समय बर्बाद कर पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।कई फरियादियों का कहना है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान हमारे क्षेत्र के थानाध्यक्ष सिर्फ मोबाइल फोन पर ही सुन ले और उनकी समस्या का समाधान कर दे तो यहां पर आने की जरूरत नहीं है।देखा जाए तो इस समय सीयूजी नंबर एक सफेद हाथी साबित हो रहा है।क्योंकि जिले के कई ऐसे थाने हैं जो दूर दराज स्थित है वहां पर तैनात थानाध्यक्ष का सीयूजी नंबर नहीं लगता।जिसका मुख्य कारण बीएसएनल है।जिले के थाना हैदरगंज,तारुन,खंडासा,कुमारगंज,मवईपटरंगा, गोसाईगंज सहित कई ऐसे थाना परिसर है जहां पर बीएसएनल का नेटवर्क ही नहीं पकड़ता। इस संबंध में एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया की यह समस्या बहुत ही गंभीर है। उन्होंने बताया कि मुख्यालय पर भी आने वाले कई फरियादियों का भी कहना है कि थानाध्यक्ष फोन नहीं उठाते है।अगर उठा ले तो यहां पर आने की जरूरत ही नहीं।उन्होंने सभी सर्किल सीओ और थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि सीयूजी पर आने वाले सभी फोनों का जवाब जरूर दें।हां अगर आप बैठक या आवश्यक कार्य में है तो बाद में निकलकर कॉल बैक करें। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे थाना क्षेत्र है जहां पर सीयूजी नंबर बीएसएनल होने के चलते नहीं पकड़ता है।

सामूहिक दुष्कर्म के दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में बदलापुर थाना अंतर्गत पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित दो अभियुक्तों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को थाना क्षेत्र के बदलापुर स्थित संग्राम बालिका इंटर कॉलेज के पास से हिरासत में लिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह द्वारा अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आतिश कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्राधिकारी बदलापुर सुनील चन्द्र तिवारी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बदलापुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में सरोज कुमार यादव पुत्र रामहित यादव निवासी ग्राम सरोखनपुर थाना बदलापुर तथा प्रिंस तिवारी पुत्र शिवकुमार तिवारी निवासी सिरसी थाना तेजीबाजार जनपद जौनपुर शामिल हैं। दोनों अभियुक्त थाना बदलापुर में बीएनएस व 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट के तहत वांछित थे।आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को न्यायालय भेज कर दिया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ एटीएम का उद्घाटन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का उद्घाटन एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह द्वारा किया गया।यह एटीएम टर्मिनल भवन के बाहर आगमन साइड में स्थापित किया गया है,जिससे आगमन करने वाले यात्रियों एवं आमजन को भी आसानी से नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।इस अवसर पर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण श्रीवास्तव, रविन्द्र सिंह, एटीसी इंचार्ज अवधेश कुमार सिंह, सीएनएस इंचार्ज अनिल शुक्ला, टर्मिनल प्रभारी जयंतो नियोगी सहित यूनियन बैंक एवं एयरपोर्ट के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।एयरपोर्ट परिसर में एटीएम की स्थापना से यात्रियों को त्वरित एवं सुलभ बैंकिंग सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी।यह पहल यात्री सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्व. चौधरी अजीत सिंह सरल एवं सादगी के प्रतिमूर्ति थे : मिर्जा जावेद सुल्तान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। किसान मसीहा स्व. चौधरी अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया गया। रालोद अर्बन कमेटी के सदस्य मिर्जा जावेद सुल्तान के कटघरा स्थित आवास पर किसान संगोष्ठी के आयोजन उपरांत मिर्जा जावेद सुल्तान के नेतृत्व में रालोद नेताओं के द्वारा सदर अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। किसान संगोष्ठी को संबोधित करते

हुए मिर्जा जावेद सुल्तान ने कहा कि स्व. चौधरी अजीत सिंह सरल एवं सादगी के प्रतिमूर्ति थे। स्व. चौधरी ने औद्योगिक सुधारों का ड्राफ्ट तैयार किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। उन्होंने सदैव किसानों के अधिकार की आवाज को बुलन्द की और बिना थके, बिना झुके समाज के हित में कार्य करते रहे। उनका जीवन हमें संघर्ष, समर्पण और सेवा की प्रेरणा देता है। आज उनके जन्मदिन पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि उनके आदर्शों पर चलकर समाज और देश की सेवा करेंगे। इस अवसर पर अशोक यादव प्रदेश सचिव, उपाध्यक्ष राम बदन सरोज, वरिष्ठ नेता सत्य नारायण यादव, जिला प्रवक्ता दयाशंकर यादव, हैदर मेहदी, साहिल आब्दी, मोहम्मद जलालुद्दीन, खिलाड़ी प्रसाद, रमी मिर्जा आदि लोग उपस्थित रहे।

रामघाट के पास पाइप में मिला साधू का शव

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।काशीराम कॉलोनी रामघाट अयोध्या के सामने स्थित एसटीपी के बगल में एक साधु व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।बताया जा रहा है कि मृतक का शव एक बड़े पाइप के अंदर पड़ा मिला।घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।सूचना पर अयोध्या कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस संबंध मे सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु प्रतीत हो रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कुछ भी कहा जा सकता है।

फेसबुक के द्वारा बोलेरो बेचने के नाम पर 95 हजार की ठगी

ब्यूरो चीफः आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुलतानपुर । फेसबुक के जरिए वाहन बेचने का झांसा देकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रसूलहा गांव निवासी मो. करीम से बोलेरो गाड़ी बेचने के नाम पर 95,848 रुपये की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताते हुए वर्दी की फोटो भेजकर भरोसा दिलाया। अलग-अलग किश्तों में गूगल-पे से रकम लेने के बाद न तो गाड़ी दी गई और न ही पैसा लौटाया गया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पीड़ित की तहरीर पर शिवगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 206 केंद्रों पर होगी परीक्षा, नकलविहीन संपादन के जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संगोष्ठी भवन में गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा–2026 को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली प्रातः 8:30 बजे से 11रू45 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 2:00 बजे से 5:15 बजे तक संचालित होगी। जनपद में कुल 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाईस्कूल में 77,042 तथा इंटरमीडिएट में 77,080 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा की सुचारु निगरानी के लिए 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 206 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रिजर्व अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए विभागीय कंट्रोल रूम नंबर 7905471191 एवं 9451962481 जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को प्रश्नपत्रों की गोपनीयता अक्षुण्ण रखने, परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने आवंटित केंद्रों पर समय से उपस्थित रहकर परीक्षा की ।

सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों (एसपीईएस) ने नियोक्ताओं पर अनुचित श्रम प्रथाओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में उन्हें अवैध स्थानांतरण, काम से वंचित करने तथा सेवा समाप्ति जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नियोक्ता कथित रूप से मनगढ़ंत आरोप लगाकर वेतन और यात्रा भत्ते का भुगतान रोक रहे हैं। संगठन के सचिव अजय चौरसिया ने बताया कि कई नियोक्ता बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 तथा अन्य श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों को धमकाने और अपमानित करने के साथ ही यूनियन गतिविधियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर कुछ मामलों में झूठी पुलिस शिकायतें दर्ज कराने का भी आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि चारों नई श्रम संहिताओं को निरस्त कर पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को प्रभावी रूप से लागू रखा जाए। साथ ही निश्चित अवधि रोजगार (फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट) के तहत सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने, बिना कारण छंटनी एवं स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाने और समय से पूर्ण वेतन व भत्तों का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम, 1976 एवं संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा एफएमआरएआई से विचार–विमर्श के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्य नियम बनाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

'एसपी चारु निगम पहली बार मीडिया से रूबरू,बोलीं–हर घटना पर मिलेगी आधिकारिक बाइट'

ब्यूरो चीफः आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुलतानपुर । जिले में पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालने के बाद आईपीएस अधिकारी चारु निगम बुधवार को पहली बार पुलिस लाइन सभागार में मीडिया से मुखातिब हुईं। परिचय बैठक के दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद स्थापित करते हुए पुलिस–मीडिया समन्वय को प्राथमिकता देने की बात कही।उन्होंने बताया कि वह वर्ष 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और प्रशिक्षण अवधि में गोरखपुर व झांसी में सेवाएं देने के साथ ही लखनऊ तथा औरैया में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुकी हैं।एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक सीओ अपने–अपने क्षेत्र में घटित घटनाओं पर मीडिया को अधिकृत बाइट उपलब्ध कराएं। साथ ही थाने स्तर से भी आवश्यक सूचनाएं समय पर साझा की जाएं,जिससे पारदर्शिता बनी रहे।नगर क्षेत्र में जाम की समस्या पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सड़क किनारे वाहन खड़े करने वाले वाहन मालिकों को पहले दो दिन की चेतावनी दी जाएगी,इसके बाद नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।अवैध खनन के मामलों पर उन्होंने कहा कि जल्द ही विस्तृत समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिले व गैर जनपद के अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख्त कदम उठाने की बात भी उन्होंने दोहराई।एसपी चारु निगम ने कहा कि पुलिस और मीडिया के बीच किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी।जो भी विषय उनके संज्ञान में आएगा,उसका तत्काल समाधान कराया जाएगा। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि जिले की किसी भी समस्या की जानकारी सीधे उन्हें दें,ताकि शीघ्र निराकरण किया जा सके।

शराब के नशे में दो सौतेले भाइयों में विवाद, छोटे भाई की मौत

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ताखा पूरब गांव में बुधवार देर रात शराब के नशे में दो सौतेले भाइयों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें छोटे भाई की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र के ताखा पूरब निवासी सुदर्शन यादव (24)का अपने सौतेले भाई अरविंद (32)से अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। बुधवार रात करीब रात दोनों शराब के नशे में थे। इसी दौरान कहासुनी शुरू हुई जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान अरविंद ने सुदर्शन को जोर से पकड़ लिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। परिजन उसे संभाल पाते, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में सनसनी फैल गई। दोनों भाई अविवाहित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही शाहगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी अरविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।इस मामले में गुरुवार को जानकारी लेने पर क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला नशे की हालत में आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है। तहरीर मिलने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

रामपुर अधिवक्ता हत्याकांड के विरोध में जौनपुर में न्यायिक कार्य का बहिष्कार, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में रामपुर में अधिवक्ता फारुक अहमद खां की न्यायालय परिसर में गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र यादव की अध्यक्षता में संघ सभागार में आयोजित आपात बैठक में घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। वक्ताओं ने कहा कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ता की दिनदहाड़े हत्या अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। यह घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में विफल साबित हो रहा है। बैठक में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर रामपुर बार एसोसिएशन के आंदोलन का समर्थन किया गया तथा पूरे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को विरोध पत्र प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम शीघ्र लागू नहीं किया गया तो वे व्यापक आंदोलन और धरना–प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।

कमिश्नर ने डीएम के साथ रुदौली तहसील व विकास खण्ड के निरीक्षण मे मिली खामियों से पेशकार निलंबित

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।कमिश्नर राजेश कुमार ने डीएम निखिल टीकाराम फुंडे के साथ गुरुवार को रुदौली तहसील परिसर का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न पटलों का बारीकी से अवलोकन किया तथा रिकॉर्ड रूम में अभिलेखों, पत्रावलियों एवं संबंधित रजिस्टरों की जांच की।उन्होंने तहसील परिसर में साफ सफाई के साथ पेयजल की व्यवस्था कराने,अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी उप जिलाधिकारी संतोष कुमार को दिए। परिसर निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने एक बुजुर्ग महिला की समस्या भी सुनीं उन्होंने संबंधित को निर्देश दिया इनकी समस्या का तत्काल निस्तारण कराया जाए।तहसील न्यायिक की पत्रावलियों के अवलोकन के दौरान अनियमितता पाए जाने पर मंडलायुक्त ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित पेशकार राघवेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी तथा अभिलेखों का सुव्यवस्थित एवं अद्यतन संधारण सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने विकास खण्ड रुदौली का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। साथ ही जनता से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित हैचरी केंद्र का भी अवलोकन किया। उन्होंने समूह की महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।इस अवसर पर सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह,अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, जिला विकास अधिकारी मह्रेंद्र देव सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ढाई लाख रुपये में तय हुआ था नवजात का सौदा

गोरखपुर, (संवाददाता)। बेलहरकला थाना क्षेत्र से हुए मासूम बच्चे के अपहरण कांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि नवजात बच्चे का सौदा ढाई लाख रुपये में तय हुआ था, जिसमें से 1.75 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका था। रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बच्चे की सकुशल बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही टीम के सदस्यों को पदक के लिए संस्तुति किए जाने की बात भी कही। एसपी ने बताया कि आठ फरवरी की शाम करीब पांच बजे पीड़िता नारायनपुर बाजार से जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी। इसी दौरान एक महिला और पुरुष ने उसके नवजात बच्चे को छीन लिया और फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट नौ फरवरी की रात में दर्ज कराई गई थी।इसके बाद मामले के खुलासे के लिए एसओजी प्रभारी अजय कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी अभिमन्यु सिंह और प्रभारी निरीक्षक बेलहरकला अनिल कुमार के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मंगलवार को बालू शासन पुल के पास से सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश यादव निवासी भलुआं थाना तर्रैया, छपरा (बिहार), वर्तमान पता विधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद य संगीता निवासी विधियानी य राजकुमार निवासी मैलानी थाना कोतवाली खलीलाबाद य पिंटू निवासी है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।